

असाधारग EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] No. 108] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1981/वैत्र 5, 1903

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1981/CHAITRA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पूष्ठ संस्था को जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधिः न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई विल्ली, 26 मार्च, 1981

सा० का० मि० 212 (अ).---राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित भावेण सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:---

"सं० आ० 115

संविधान (राजस्व वितरण) आवेश, 1981

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित आवेश करते हैं, अर्थात् :—

- 1. इस मावेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्य वितरण) म्रावेश, 1981 है।
- 2. साधारण खण्ड प्रधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस प्रादेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय प्रधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
 - 3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार---
- (क) नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्विष्ट प्रत्येक राज्य के धाजस्व के महाग्रता भनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (6) मे प्रत्येक के सामने विनिर्विष्ट राभियां उन स्तम्भों में वर्णित 1502 G1/80

सेक्टरों भौर सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों पर 1 अप्रैल, 1980 से घारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षे में, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जो राजस्व भौर पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं :→

REGISTERED No. B. (D) 72

सारसी

		·		
स्यायिक प्रशासन	पुलिस प्रशासन	जेल प्रशासन	राजस्य जिला धौ र जनजाति प्रशासन	स्टाम्प, रजिस्ट्री- करण भौर
				खजाना
				प्रशासन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रोध्य प्रदेश	20.00	338.00	57.21	171.00	
भसम	6.19	412.35		193.55	
बिहार		496.24	62.93	18 5.00	
हिमाचल प्रदेश	1.40	65.92		19.66	
जम्मू-कथमीर		133.21	11.00		
केरल	0.56			7.45	

(517)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्य प्रवेश	8 18	467.94	139.28	377.50	6.00
मणिपुर	10.50	113.53	25-17	100.00	
मेचालय		17.50	12.20	28.50	
भागालैण्ड	27.00	50.00		12.80	• •
उड़ी सा	2-00	148.10	104-97	175.07	
राजस्थान	20.00	258.35	8.00	79-25	12.00
सिक्किम			7.00		
तमिलनाडु	1.00	373.38	340.00	3.28	
त्रिपुरा	25.85	33.07		13.50	2.00
उत्तर प्रदेश	163.84	1749.73	304.48	405.45	195 79
पश्चिमी बंगाल	110.05	250.08		29.50	

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट भीर केन्द्रीय सरकार द्वारा भनुमोदिस संक्टरों भीर सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक रुपय, जैसा कि उक्त वर्ष के लेखाओं में प्रकट होता है, उक्त प्रशासन के सामने ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार प्रधिक संदत्त रकम ऐसी राशिया राशियों के विषद्ध समायोजित की जाएंगी जो उसी प्रयोजन या किसी प्रन्य प्रयोजन के लिए किसी प्रस्वातवर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए।

(स्र) इस संबंध में विक्त भाषोग की सिफारिशो के भनुसार, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्विष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता भनुवान के रूप में 1 भन्नैल, 1979 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, उस प्रत्येक राज्य द्वारा नए उधार लेने भीर उद्यार देने के कारण पुत्र क्याज वायित्व के महे, सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्विष्ट राशियों हैं :—

सारसी

राज्य			(लार	प्र रुपयों में)
हिमाचल प्रवे				5,48
मणिपुर				40.93
मेषालय				5.28
नागालैण्ड				10,95
अ्डी सा				27.3 7
सिक्किम				1.64
ब्रिपुरा		_		7.15

परन्तु यदि उस वर्ष के खातों में प्रकट किए गए वास्तविक उद्यार सेने भीर उद्यार देने के अंक या उद्यार सेने पर अयाज की ं, बरें, उपर विनिद्दिष्ट अनुवानों के अवद्यारण करने में हिसाब में सिए गए सुसंगत अंकों से भिन्न हैं, तो इस प्रकार संदत्त अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या रामियों के प्रति, जो उसी या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी पश्चात्वर्तों वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए, समायोजित की जाएगी ।

(2) 1 अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ होने नाले वित्तीय वर्ष में छप-पैरा (1) के खण्ड (क) श्रीर (ख) के अधीन किसी राज्य को संदेग कोई राशि या राशियां उस राशि या राशियों के अतिरिक्त होनी या होंगी जो संविधान (राजस्व वितरण) श्रावेश, 1979 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के श्रनुसरण मे उक्त वित्तीय वर्ष में उस राज्य को सदेय हो ।

नीलम सजीव रेंद्कि, राष्ट्रपति।"
[सं० फा० 19 (1)/81-एल-1]
६० बेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, मचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1981.

G.S.R. 212(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 115

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1981

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

- 1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1981.
- 2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
- 3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1980, as grants-in-aid of the revenues of:—
 - (a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure, of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns:—

TABLE

		For up	_	n of stangto	ındards
State	Judicial adminis- tration	Police adminis- tration		Revenue, s- District and Tribal adminis trations	Regis- tration and - Trea-
		(Rs. in l	akhs)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Andhra Pradesh	20.00	338.00	57.21	171.00	
Assam	6.19	412.35		193.55	
Bihar		496.24	62.93	185.00	
Himachal Pradosh	1.40	度 65.92		19.66	

	-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jammu and Kashn	nir	133.21	11.00		·
Kerala	0.56			7.45	
Madhya Pradesh	8.18	467.94	139.28	377.50	6.00
Manipur	10.50	113.53	25.17	100.00	
Meghalaya		17.50	12,20	28.50	
Nagaland	27.00	50.00		12.80	
Orissa	2,00	148.10	104.97	175.07	
Rajasthan	20.00	258.35	8.00	89,25	12.00
Sikkim			7,00		
Tamil Nadu	1.00	373.38	340,00	3.28	
Ггірига	25,85	33.07		13.50	2.00
Uttar Pradesh	163.84	1749.73	304.48	405,45	105.79
West Bengal	110.05	250.08		29.50	

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government:

Provided further that if the actual expenditure on approved programme or programmes relating to any administration, as revealed in the accounts of that year, is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1979, as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State	_		<u> </u>		(Rs.	n lakhs)
(1)		 	- —		(2)	
Himachal Pradesh		 •				5.48
Manipur						40.93
Meghalaya						5.28
Nagaland						10.95
Orissa						27.37
Sikkim						1.64
Тгірига						7.15

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of that year, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1980 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1979.

N. SANJIVA REDDY,
President."

[No. F. 19(1)/81-L.I.]

R.V.S. PERI SASTRI, Socy